राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

ओपनिंग टेस्ट में रोहित पास, जमाया शतक

>> 14

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 115

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 3 अक्टूबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

बंदियों के हुनर ने अगरबत्ती की राख को दिया आकार

ग्रेटर नोएडा : स्टार्टअप के तहत दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 100 से ज्यादा मंदिरों से हर महीने 800 किलो अगरबत्ती की राख एकत्र की जा रही है। जिससे देश की राजधानी से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर की जिला जेल में बंदी सुंदर मूर्तियां गढ़ रहे हैं। (पेज-10)

जागरण विशेष

गोबर और गोमूत्र से भी उड़ सकेगा रॉकेट!

जमशेदपुर : गोमूत्र व गोबर के मिश्रण से हाइड्रोजन गैस बनती है। परिष्करण कर इसका इस्तेमाल रॉकेट के प्रोपेलर में ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआइटी) आदित्यपुर में इस पर शोध चल रहा है। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

आर्म्स एक्ट को संशोधित कर और सख्त बनाएगी सरकार

नई दिल्ली : भारत में सीमा पार से अवैध हथियारों की आमद रोकने को केंद्र सरकार आर्म्स एक्ट को और कड़ा बनाएगी। सूत्रों के अनुसार, चीन से हथियारों की तस्करी करके भारत लाया जाता है, जिनका इस्तेमाल पूर्वोत्तर में नक्सली संगठन करते हैं। पाकिस्तान से भी हथियारों को तस्करी होती है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

सुरक्षा परिषद में भारत का न होना यूएन की साख पर सवाल

वाशिंगटन : भारत ने मंगलवार को कहा कि उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। इसके लिए भारत का पक्ष मजबूत है। भारत के बिना सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाशिंगटन में अमेरिकी थिंक टैंक 'सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज' में विदेश नीति पर भाषण देने के बाद लोगों से यह बात कही।

स्पोर्ट्स ▶ पृष्ठ 14

कपिल देव ने सीएसी प्रमुख के पद से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली : कपिल देव ने हितों के टकराव के मुद्दे पर तीन सदस्यीय एडहॉक क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल इस समिति के प्रमुख थे। बीसीसीआइ से जुड़े एक सूत्र ने बताया, 'हां, कपिल देव ने सीएसी प्रमुख के पद से अपना इस्तीफा भेज दिया है।

आजकल ▶ पृष्ठ 16

ट्विटर और ट्वीटडेक हुए ठप, हजारों यूजर प्रभावित

वाशिंगटन : माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर बुधवार को एक बार फिर ठप हो गई। जिसके चलते पूरी दुनिया के यूजर्स डैशबोर्ड मैनेजमेंट प्लेटफार्म ट्वीटडेक या ट्विटर इस्तेमाल नहीं कर सके। हालांकि मोबाइल एप के साथ यह समस्या नहीं है। बता दें कि ट्वीटडेक सिंगल स्क्रीन पर ट्विटर फीड्स को मॉनीटर और मैनेज करने के लिए एक वेब और डेस्कटॉप सॉल्यूशन है।

निजाम के धन पर पाक का दावा खारिज, ब्रिटिश कोर्ट का भारत के पक्ष में फैसला

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटिश हाई कोर्ट से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। विभाजन के बाद हैदराबाद के तत्कालीन सातवें निजाम के धन को लेकर पाकिस्तान के साथ चल रही दशकों पुरानी कानूनी लड़ाई में कोर्ट ने बुधवार को भारत और निजाम के उत्तराधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। उस समय यह रकम करीब 10,07,940 पाउंड और नौ शिलिंग की थी जो अब बढ़कर करीब 3.5 करोड़ पाउंड (300 करोड़ रुपये) हो गई है। यह रकम लंदन स्थित नैटवेस्ट बैंक पीएलसी में जमा है।

हैदराबाद के तत्कालीन सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान ने 1948 में उक्त रकम ब्रिटेन में पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहीमटूला को हस्तांतरित की थी। तभी से यह रकम नैटवेस्ट बैंक पीएलसी के उनके खाते में जमा है।

पाक की दलीलें : पाकिस्तान इस रकम पर दो दलीलों के आधार पर अपना दावा कर रहा था। पहली, सातवें निजाम ने यह रकम हथियार और पाकिस्तान की मदद हासिल करने के एवज में हस्तांतरित की थी। दूसरी, यह रकम भारत के हाथ में न चली जाए इसलिए हस्तांतरित की गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने दो और दलीलें दी थीं। पहली, यह गैरन्यायिक मामला है क्योंकि रकम का हस्तांतरण दो सरकारों के बीच था। दूसरी, 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय गैरकानूनी था, इसलिए इस रकम पर भारत और आठवें निजाम का दावा नहीं बनता।

निजाम ने भी किया था दावा : हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के बाद 1950 में सातवें निजाम ने इस रकम पर अपना दावा किया था। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उनका दावा खारिज कर दिया था। पाकिस्तान के सॉव्रिन इम्यूनिटी का दावा करने से केस की प्रक्रिया रुक गई थी, लेकिन 2013 में पाकिस्तान ने रकम पर दावा करके सॉव्रिन इम्यूनिटी खत्म कर दी थी। जिसके बाद मामले की कानूनी प्रक्रिया फिर शुरू हुई थी। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई में सातवें निजाम के वंशजों और हैदराबाद के आठवें निजाम प्रिंस मुकर्रम जाह तथा उनके छोटे भाई मुफ्फखम जाह ने भारत सरकार से हाथ मिला लिया था।

- सातवें निजाम की ब्रिटेन में जमा 3.5 करोड़ पाउंड की रकम का मामला
- निजाम ने 1948 में तत्कालीन पाक उच्चायुक्त के खाते में जमा कराई थी राशि

सातवें निजाम उस्मान अली खान (काले कोट में)। फाइल फोटो

ऐसे खारिज हुई पाक की दलीलें : लंदन की रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के जज जस्टिस मार्कस स्मिथ ने बुधवार को अपने फैसले में कहा, 'धन पर सातवें निजाम का अधिकार था और अब सातवें निजाम के उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले जाह भाइयों तथा भारत का धन पर अधिकार है।' अदालत ने पाकिस्तान द्वारा हैदराबाद को हथियारों की आपूर्ति की बात तो स्वीकार की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उक्त रकम के हस्तांतरण और हथियारों की आपूर्ति में संबंध का कोई साक्ष्य नहीं है। अदालत ने पाकिस्तान की यह दलील भी मानी कि भारत के हाथों में जाने से रोकने के लिए यह रकम स्थानांतरित की गई होगी, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार करने से इन्कार कर दिया कि रकम ट्रस्ट के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी। कोर्ट ने पाकिस्तान के दूसरे देश से जुड़ी गतिविधि के सिद्धांत और गैरकानूनी होने के आधार पर प्रभावी नहीं होने के तर्क को भी खारिज कर दिया।

जीवनकाल में निपटारे पर खुशी : आठवें निजाम की ओर से केस लड़ रहे 'विदर्स एलएलपी' के पार्टनर पॉल हेविट ने कहा कि जब विवाद उठा था तो हमारे मुवक्किल बच्चे थे। अब वह 80 साल से अधिक उम्र के हैं। यह राहत की बात है कि इस विवाद का निपटारा उनके जीवनकाल में ही हो गया। बता दें कि प्रिंस मुकर्रम जाह इस समय इस्तांबुल में रह रहे हैं, जबकि मुफ्फखम जाह लंदन में रहते हैं।

पाक ने हथियार आपूर्ति की बात स्वीकारी : भारत सरकार की कानूनी टीम में शामिल वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि इतिहासकारों को पाकिस्तान की इस खुली स्वीकारोक्ति में रुचि होगी कि वे हथियारों की आपूर्ति कर रहे थे। यह बहुत ही दिलचस्प पहलू है जिसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया गया है।

निजाम के पोते ने की थी पाक से समझौते की कोशिश

सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान के हैदराबाद में रहने वाले पोते नवाब नजफ अली ने ब्रिटिश कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए बताया कि उन्होंने 2008 में पाकिस्तान सरकार के साथ कोर्ट से बाहर समझौते की कोशिश की थी, लेकिन पड़ोसी देश ने उनकी पेशकश पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। उन्होंने कहा, 'मैंने भारत में पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त से बातचीत शुरू की थी। इसके बाद मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिला था। उस समय प्रणब मुखर्जी विदेश मंत्री थे। हम इन सभी लोगों से मिले थे और उस समय हम सभी पाकिस्तान से कोर्ट के बाहर समझौता करना चाहते थे।' प्रिंसेस इस्रा ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है।

खुले में शौच से मुक्त हुआ देश

लक्ष्य पूरा ▶ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर पीएम ने किया एलान

कहा, जनता ने आगे बढ़कर अभियान को सफल बनाया

जागरण ब्यूरो, अहमदाबाद

पांच साल पहले तक असंभव सा लगने वाला एक लक्ष्य आज पूरा हो चुका है। देश खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त हो गया है। आजादी के बाद की इस सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति का बिगुल बजाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को किला फतह करने का एलान किया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर साबरमती पहुंचे मोदी ने रिवरफ्रंट पर आयोजित समारोह में देश विदेश के राजदूतों, विचारकों, गांधीवादियों, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, केंद्रीय व गुजरात मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा देश के 20 हजार सरपंचों की मौजूदगी में कहा, आज गांधीजी का सपना पूरा हुआ। देश खुले में शौच से मुक्त हो गया है। बीते पांच साल में देश में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं।

मोदी ने कहा, गुजरात चक्रधारी मोहन व चरखाधारी मोहन की धरती है। पांच साल पहले लालकिला से किए गए एक अह्वान को देश के करोड़ों लोगों ने अभियान बना दिया। मोदी ने कहा जीवन में कई बार गांधी आश्रम आना हुआ। यहां आने पर हर बार उन्हें बापू का सानिध्य महसूस हुआ, लेकिन इस बार उन्हें नई ऊर्जा मिली। साबरमती का तट आज देश की स्वच्छता का साक्षी बन गया। लोगों ने स्वयं खुले में शौच जाना बंद कर इसमें भागीदारी निभाई। कहीं पर बेटियों ने शादी के लिए शौचालय की शर्त रखी तो शौचालय को इज्जत घर बना दिया। मोदी ने गांधी जयंती पर एक डाक टिकट व 150 रुपये का चांदी का सिक्का जारी किया।

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, बापू ने गुजरात से दुनिया को स्वच्छता का संदेश दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीजी के सपने को पूरा कर दिखाया। उपमुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल ने कहा कि गांधी जयंती को भारत ने स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया। मोदी ने गांधीजी का स्वच्छता का सपना उनकी 150वीं जयंती पर पूरा कर दिया। मोदी आजादी के बाद एक सामाजिक क्रांति के अगुआ बने। मोदी ने 2014 में पीएम बनने के बाद स्वच्छता अभियान व हर घर शौचालय अभियान का एलान किया था।

इन्हें बताया स्वच्छता का सिपाही : स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण अभियान 2019 में तमिलनाडु सबसे श्रेष्ठ रहा। सर्वेक्षण में सबसे अधिक यूपी से एक करोड़ से अधिक लोगों ने भागीदारी की, जिसके लिए मंत्री भूपेंद्र सिंह को राज्य का अवार्ड प्रदान किया गया। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले और महाराष्ट्र के तावसी गांव को श्रेष्ठ स्वच्छता अवार्ड दिया गया। स्वच्छता के लिए अभियान चलाने वाली मेघालय की सरपंच लिंम लिंगती लिंगखोई और बिहार की शर्मिला देवी को श्रेष्ठ सरपंच चुना गया। वहीं निबंध लेखन में पुडुचेरी के एस. विश्वा, गोवा के शेम फर्नांडिस, छत्तीसगढ़ की करीना खातून को सम्मानित किया गया।

अहमदाबाद में बुधवार को साबरमती रिवरफ्रंट पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम के दौरान एक बच्चे को दुलारते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एएनआइ

दुनिया में बढ़ा भारत का सम्मान

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के लिए पीएम मोदी को सम्मानित करने के लिए गुजरात भाजपा ने कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत की इज्जत और ताकत बढ़ गई है। अमेरिका के ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की इस बढ़ी हुई ताकत को अनुभव किया। आज भारतीय पासपोर्ट का सम्मान और इसकी ताकत बढ़ गई है। इस बदलाव को सब महसूस कर सकते हैं। मोदी ने 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम की सफलता के लिए ह्यूस्टन के मेयर सिल्वेस्टर टर्नर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार भी जताया।

150वीं जयंती पर देश ने महात्मा गांधी को किया याद

नई दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश ने महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर याद किया। इस मौके पर दिल्ली में बापू की समाधिस्थल राजघाट समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। (पेज-3 भी देखें)

150वीं जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देश ने किया याद पेज>>3

बापू को नमन (विशेष आयोजन) पेज>>5

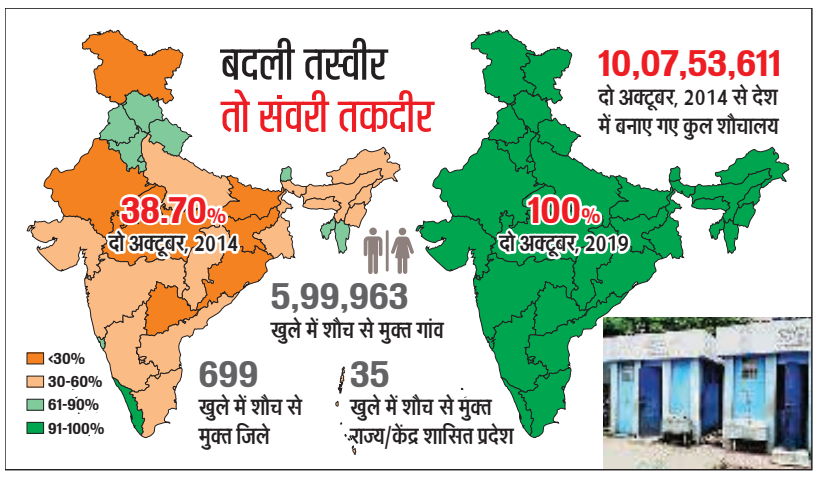

देश के पहले टॉयलेट कॉलेज से 3,200 स्वच्छता कर्मियों ने पाया प्रशिक्षण

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के पहले टॉयलेट कॉलेज में 3,200 स्वच्छता कर्मियों ने एक साल तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अगस्त 2018 में स्थापित हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज स्वच्छता कर्मियों को उनके कौशल को बढ़ाने और कार्य संबंधी खतरों के प्रति जागरूक बनाने में मदद करता है।

भारत ने ललित मोदी और उनकी पत्नी के स्विस बैंक खातों का ब्योरा मांगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश में जमा कालेधन का पता लगाने के लिए सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। भारत सरकार के आग्रह के बाद स्विट्जरलैंड ने आइपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी व उनकी पत्नी मीनल को नोटिस भेज दस दिन में जवाब देने को कहा है। वित्तीय हेराफेरी का पता लगाने के लिए हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत स्विट्जरलैंड के फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफटीए) ने ललित और मीनल का नाम दिया है। हाल के महीनों में भारत के अनुरोध पर कई लोगों के बारे में जानकारी मांगी जा चुकी है।

2010 से लंदन में रह रहे ललित के खिलाफ पहले से ही मनी लांड्रिंग की जांच चल रही है हालांकि वह इससे इन्कार करते रहे हैं। एक अक्टूबर को जारी नोटिस में ज्यादा विवरण तो नहीं दिया गया है। इससे पहले भी स्विट्जरलैंड 2016 में ऐसा ही नोटिस जारी कर चुका है। लेकिन यह पता नहीं लगा कि स्विट्जरलैंड ने भारत से ज्यादा जानकारी साझा की थी या नहीं। हालांकि इन दोनों को सुनवाई का अधिकार दिया गया था। हाल ही में एफटीए ने भारत सरकार को कई ऐसे लोगों की जानकारी दी है जिन पर कर संबंधित मामलों की जांच चल रही है।

टैक्स हैवन कहे जाने वाले स्विट्जरलैंड ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में कुछ देशों के साथ जानकारी साझा करने का समझौता किया है। स्विस कानून के मुताबिक, कोई भी जानकारी साझा करने की एक प्रक्रिया है। अब दोनों देशों के बीच ऑटोमैटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज मकैनिजम के चलते भारत के पास भारतीयों के स्विस अकाउंट्स की जानकारी है।

पाकिस्तानी आतंकी भारत में हमले की फिराक में : अमेरिका

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका ने भारत को आगाह किया है कि पाकिस्तानी आतंकी हमले की फिराक में हैं। वे जम्मू-कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के कारण भारत में आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर शिकंजा कसे तो इन हमलों को रोका जा सकता है।

अमेरिका के हिंद-प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक रक्षा सचिव रैंडल श्राइवर ने मंगलवार को यहां कहा, 'कश्मीर पर भारत सरकार के नए कदम से कई देशों को आशंका है कि आतंकी संगठन सीमा पार हमलों को अंजाम दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि चीन इस तरह का कोई संघर्ष चाहेगा या इसका समर्थन करेगा।' श्राइवर ने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का चीन द्वारा समर्थन किए जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल पर यह जवाब दिया। भारत ने गत पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त कर दिया था। श्राइवर ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह (कश्मीर मसले पर चीन का पाकिस्तान को समर्थन) बहुत हद तक कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन है। उन्होंने (चीन) पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय मंच पर समर्थन किया है। कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने या नहीं ले जाने के संबंध में कोई चर्चा हुई तो चीन इसका समर्थन करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन इससे ज्यादा कुछ करेगा।'

चीन से स्थिर संबंध चाहता है भारत : अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के शीर्ष अधिकारी श्राइवर ने कहा कि चीन के पाकिस्तान से लंबे समय से संबंध हैं और उनकी भारत के साथ प्रतिद्वंद्विता बढ़ रही है। जबकि भारत अपने पड़ोसी चीन के साथ स्थिर संबंध चाहता है।

पाक की ओर चीन के झुकाव का कारण बताया : भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के मौजूदा अमेरिकी दौरे का जिक्र करते हुए अमेरिका के सहायक रक्षा सचिव श्राइवर ने कहा, 'उनके साथ विचार-विमर्श चल रहा है। हमने चीन के साथ संबंधों के बारे में चर्चा की। वे चीन के साथ स्थायी संबंध चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि चिंताएं और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि कश्मीर समेत कई मसलों के कारण चीन का झुकाव पाकिस्तान की ओर है।'

- सहायक रक्षा सचिव ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध है मुख्य कारण

रैंडल श्राइवर फाइल फोटो

कश्मीर पर भारत को मिला सऊदी अरब का साथ

नई दिल्ली, एएनआइ : जम्मू-कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का इस्लामिक कार्ड फेल हो गया है। प्रमुख इस्लामिक देश सऊदी अरब ने भी इस मसले पर भारत के रुख का समर्थन कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के साथ बुधवार को रियाद में दो घंटे तक चली बैठक के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भारत के रुख और उसके उठाए कदमों को वह बखूबी समझते हैं।

उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि डोभाल और प्रिंस सलमान के बीच बैठक में द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े कई मसलों पर विभिन्न पहलुओं से विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने बताया, 'चर्चा के दौरान जम्मू-कश्मीर का मसला भी उठा जिस पर सऊदी प्रिंस ने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में भारतीय रुख और कार्रवाई के बारे में समझते हैं।' सऊदी अरब ने यह प्रतिक्रिया ऐसे समय व्यक्त की है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने जाते समय कश्मीर पर समर्थन जुटाने के मकसद से दो दिन सऊदी अरब में रुके थे। यही नहीं, वह न्यूयॉर्क भी सऊदी प्रिंस के विशेष विमान से ही गए थे। महासभा की बैठक के दौरान भी पाकिस्तान इस मसले पर अन्य देशों का समर्थन जुटाने में विफल रहा था।

सूत्रों ने आगे कहा कि डोभाल की सऊदी अरब की यह महत्वपूर्ण यात्रा आपसी हितों के मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सर्वोच्च स्तर पर जारी विचार-विमर्श को रेखांकित करती है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच गहरे जुड़ाव को और मजबूत करेगी और सहयोग के खास क्षेत्रों की पहचान में मदद करेगी। खासकर तब जबकि क्राउन प्रिंस के विजन 2030 के मुताबिक सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था के विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब ने हाल ही में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की थी। डोभाल ने सऊदी प्रिंस के अलावा अपने समकक्ष मुसैद अल अल्बान से भी मुलाकात की।

- सऊदी प्रिंस ने कहा, समझते हैं जम्मू-कश्मीर में भारत के कदम की जरूरत
- डोभाल-प्रिंस के बीच दो घंटे चली बैठक, पाक का इस्लामिक कार्ड फेल

अजीत डोभाल प्रिंस सलमान (फाइल)

रैंकिंग

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को जारी की स्टेशन स्वच्छता सर्वे-2019 की रिपोर्ट, उत्तर-पश्चिम रेलवे को मिला सबसे स्वच्छ जोन का दर्जा, उत्तर-मध्य रेलवे जोन स्वच्छता रैंकिंग में सबसे नीचे

जयपुर, जोधपुर सबसे स्वच्छ स्टेशन, प्रयाग, आगरा फिसड्डी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

स्टेशन स्वच्छता सर्वे-2019 में जहां जयपुर, जोधपुर समेत राजस्थान के तीन रेलवे स्टेशनों को स्वच्छता के लिए सर्वाधिक शानदार कार्य करने वाले स्टेशनों के तौर पर मान्यता मिली है। साथ ही टॉप-10 में छह स्टेशन आने के कारण उत्तर-पश्चिम रेलवे को सबसे स्वच्छ जोन का दर्जा मिला है, वहीं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जोन के अधिकांश स्टेशनों के घटिया प्रदर्शन के कारण संपूर्ण उत्तर-मध्य रेलवे जोन स्वच्छता रैंकिंग में सबसे नीचे चला गया है।

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने गांधी जयंती के अवसर पर तीसरे पक्ष द्वारा कराए गए इस नवीनतम सर्वेक्षण को जारी किया। इस बार का सर्वेक्षण नए मानदंडों के आधार पर किया गया है। लिहाजा पिछले सर्वे से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। परंतु इतना बताना जरूरी है कि पिछले वर्ष के सर्वे में भी राजस्थान का जोधपुर स्टेशन ही पहले नंबर पर रहा था, जबकि इस बार जयपुर ने उसका स्थान लेकर उसे दूसरे नंबर पर खिसका दिया है। इस बार राजस्थान के ही एक अन्य स्टेशन दुर्गापुरा को तीसरे सबसे स्वच्छ स्टेशन के तौर पर सर्वे में जगह मिली है। रेलवे जोन के हिसाब से ये तीनों स्टेशन उत्तर-पश्चिम रेलवे (एनडब्लूआर) में आते हैं।

दूसरी ओर उत्तर प्रदेश से संबंधित उत्तर-मध्य (एनसीआर) रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, को सबसे अस्वच्छ स्टेशनों वाले जोन के तौर पर फजीहत झेलनी पड़ी है। इनमें प्रयाग स्टेशन को रैंकिंग में 76वां स्थान मिला है। जबकि इलाहाबाद 82वें और वाराणसी 86वें नंबर पर है। कानपुर सेंट्रल को 267वां तथा मडुआडीह को 272वां स्थान मिला है। 349 पर झांसी 385 पर महोबा और 398 पर बांदा स्टेशन की रैंकिंग और भी बुरी है। मिर्जापुर को 404वां तथा फतेहपुर को 417वां तथा मानिकपुर को 424वां स्थान मिला है। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चित्रकूटधाम कर्वी 495वें, जबकि वैश्विक पर्यटन के लिहाज से सर्वाधिक अहम ताजनगरी से संबंधित आगरा कैंट स्टेशन 503वें पायदान पर है।

स्वच्छता में इस जोन के स्टेशनों की सबसे खराब रैंकिंग इसलिए आश्चर्यजनक है क्योंकि अभी पिछले वर्ष ही प्रयागराज में ऐतिहासिक रूप से सफल महाकुंभ का आयोजन हुआ था और सफाई को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे। टॉप-10 स्वच्छ स्टेशनों में उत्तराखंड के सिर्फ हरिद्वार स्टेशन को जगह मिली है। जबकि बाकी में सूरतगढ़, उदयपुर और अजमेर जैसे राजस्थान के ही अन्य स्टेशनों के नाम हैं।

सर्वे में शामिल कुल 720 स्टेशनों में इस बार 109 उपनगरीय स्टेशनों को भी शामिल किया गया है। इनमें तीन उपनगरीय स्टेशनों-अंधेरी, विरार तथा नौगांव को रैंकिंग में सर्वोपरि स्थान मिला है।

यही नहीं, इस बार स्टेशनों की ग्रीन स्कोरिंग भी की गई है। जिसमें 100 के कुल स्कोर पर स्टेशन पर हरियाली के स्कोर को दर्शाया गया है। 50 से अधिक स्कोर वाले हरित स्टेशनों में उत्तर भारत में जालंधर सिटी को 76.4 स्कोर, कटरा स्टेशन को 75.5, हावड़ा 75.1, अजमेर को 73.8 तो प्रयागराज को 59.4 और लखनऊ को 56.7 स्कोर मिला है। जबकि देहरादून को 51.3 अंक प्राप्त हुए हैं। बिहार के छपरा, राजगीर, बक्सर और उप्र के मथुरा ने भी इसमें जगह बनाई है। दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, यशवंतपुर, पुणे, नागपुर जैसे के कई स्टेशनों ने भी 50 फीसद से अधिक स्कोर प्राप्त किया है।

- 720 स्टेशनों में राजस्थान के स्टेशन रहे सबसे आगे
- हरियाली की स्कोरिंग के साथ इस बार 109 उपनगरीय स्टेशन भी सर्वे में शामिल

प्रतीकात्मक

राजस्थान में भी पान मसाले पर पाबंदी

नईदुनिया, जयपुर

राजस्थान सरकार ने मैग्नेशियम कार्बोनेट, निकोटिन, तंबाकू और मिनरल ऑयल से बने पान मसाले और सुगंधित सुपारी के उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन और बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाया गया है। महाराष्ट्र और बिहार के बाद यह प्रतिबंध लगाने वाला राजस्थान देश का तीसरा राज्य है। राजस्थान का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गुरुवार से इन उत्पादों के नमूने लेना शुरू करेगा और जांच के बाद जिन उत्पादों में उक्त पदार्थ पाए जाएंगे, उन पर रोक लगा दी जाएगी।

राज्य में तंबाकू से बने गुटखे पर पहले से ही रोक है। कोर्ट के आदेश से लगे प्रतिबंध के बाद पान मसाला कंपनियों ने तंबाकू और पान मसाला अलग-अलग बेचना शुरू कर दिया था। ऐसे में इस प्रतिबंध का कोई खास असर नजर नहीं आ रहा था। कांग्रेस के घोषणापत्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बार के बजट भाषण में इसे नियंत्रित करने की कार्ययोजना बनाने की घोषणा हुई थी। इसी के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटिन, तंबाकू और मिनरल ऑयल से बने पान मसाले और सुगंधित सुपारी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दो अक्टूबर (गांधी जयंती) को जारी कर दिया।

राज्य के जनस्वास्थ्य निदेशक और खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. केके शर्मा ने बताया कि विभागीय टीमों ने पिछले दिनों पान मसाले और सुपारी के 310 नमूने लिए थे। इनमें से 119 स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाए गए थे। इसके बाद सरकार को इन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भेजा गया था।

इंडियन अस्थमा केयर सोसायटी के सचिव धर्मवीर कटेवा ने कहा कि सरकार हर वर्ष करीब 1160 करोड़ रुपये तंबाकू जनित बीमारियों के इलाज पर खर्च करती है। यह बात सरकार ने खुद विधानसभा में स्वीकार की है। हर रोज तंबाकू जनित रोगों से सैकड़ों लोगों की मौत होती है। ऐसे में सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है।

- महाराष्ट्र और बिहार सरकारों ने भी हाल ही में लगाया है प्रतिबंध
- कांग्रेस ने घोषणापत्र में ऐसी सामग्री को नियंत्रित करने का किया था वादा